

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 154**

**18 जुलाई, 2018 को उत्तर के लिए**

**कच्चे इस्पात का उत्पादन-लक्ष्य**

**154. डॉ. शशिकला पुष्पा रामास्वामी:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपनी राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में 2030-31 तक 300 मैट्रिक टन कच्चे इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन पहलुओं का ब्यौरा क्या है, जिन पर पर्याप्त और विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है; और
- (घ) इस संदर्भ में सेलम इस्पात संयंत्र को सौंपी जाने वाली/सौंपी गई भूमिका का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री**

**(श्री विष्णु देव साय)**

(क) और (ख): जी नहीं। सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में वर्ष 2030-31 तक क्रूड इस्पात क्षमता को 300 एमटी (उत्पादन की नहीं) तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। संबंधित उत्पादन क्षमता 255 एमटी होगी।

(ग): सरकार ने इस्पात उत्पादन की क्षमता को प्रोत्साहित करने और इस्पात खपत को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- i) राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 लागू की गई।
- ii) सरकारी खरीद में घरेलू निर्मित लोहा और इस्पात उत्पादों को वरीयता प्रदान करने की नीति (डीएमआई एंड एसपी) लागू की गई।
- iii) सार्वजनिक/सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाओं में डिजाइन और विनिर्देशन तैयार करते समय संपूर्ण जीवन लागत विश्लेषण को शामिल करने के लिए सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया।
- iv) इस्पात मंत्रालय ने इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए आईएनएसडीएजी, एचएससीएल और अपने सीपीएससी के माध्यम से विभिन्न पहल शुरू की हैं, यथा- कम लागत वाले घरों, पर्वतीय क्षेत्रों एवं भूकंपीय क्षेत्रों में अवसंरचनागत विकास के लिए अधिक इस्पात खपत के ढांचों और कम लागत वाले "आंगनबाड़ी केंद्रों" इत्यादि के प्रोटोटाइपों का विकास करना ।

(घ): इस संबंध में सेलम इस्पात संयंत्र को कोई विशेष भूमिका नहीं सौंपी गई है।

\*\*\*\*\*